nidm

Resilient India - Disaster free India

सत्यमेव जयते

टाइडिंग्स

एनआईडीएम पत्रिका–01/2025
अक्टूबर-दिसम्बर 2025

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वेबसाइट https://nidm.gov.in

/nidmmhaindia | /nidmmhaindia | /nidmmhaindia | /nidmindia | /nidmmhaindia

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान संबंधी जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत भारत और इस क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में भूमिका निभाने के दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इस दिशा में जो प्रयास वर्ष 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र (एनसीडीएम) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी, उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में फिर से नामित किए जाने के बाद और अधिक गति प्राप्त हुई।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन एवं पॉलिसी एडवोकेसी से संबंधित नोडल जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय एजेंडा के केंद्र में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान का मानना है कि सभी हितधारकों की सहभागिता से "रोकथाम की संस्कृति" को बढ़ावा देकर ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण संभव है। एनआईडीएम केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, देश-विदेश की शैक्षणिक, अनुसंधान एवं तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से कार्य करता है।

एनआईडीएम को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अलग-अलग पहलुओं पर कार्य करने वाले बहुआयामी विषयों के पेशेवरों की टीम पर गर्व है। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को सुगम बनाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत, संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें क्लास रूम, सेमिनार हॉल, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर एक सुव्यवस्थित और समृद्ध पुस्तकालय भी है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एनआईडीएम विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को क्षमता निर्माण में भी सहयोग प्रदान करता है। संस्थान का लक्ष्य आपदा रोकथाम एवं तैयारी के लिए सभी स्तरों पर क्षमता का विकास कर एक आपदा-रोधी भारत का निर्माण करना है।

NIDM पत्रिका 01/2025

अक्टूबर-दिसम्बर 2025

संपादकीय मंडल

प्रधान संपादक
श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

संपादक
डॉ. अजिंदर वालिया
एसोसिएट प्रोफेसर

संपादकीय सहायता
(डिजाइन एवं प्रस्तुति)
सुश्री नाज़िया खान
वरिष्ठ परामर्शदाता, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

तकनीकी सहायता और प्रकाशन
डॉ. रविन्द्र सिंह
वरिष्ठ परामर्शदाता
सुश्री सुप्रीता एमके, परामर्शदाता

अनुवादक
संजय कुमार
परामर्शदाता, राजभाषा

विषय सूची

1.	संदेश	2
2.	आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम	3
3.	सम्मेलन / कार्यशाला / सेमिनार	13
4.	अन्य क्रियाकलाप	16
5.	परियोजना संबंधी क्रियाकलाप	21
6.	विषयगत दृष्टिकोण	23
7.	एनआईडीएम प्रकाशन	31

आंतरिक विषय-वस्तु

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 5वां समग्र पाठ्यक्रम
06-17 अक्टूबर 2025, दिल्ली 3

आपदा के समय महिलाओं की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6-8 नवंबर 2025, चंडीगढ़ 5

आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 10-12 अक्टूबर 2025, बेंगलुरु 13

अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) 2025
19 अक्टूबर 2025, दिल्ली 16

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

कार्यकारी निदेशक का संदेश

प्रिय पाठकों,

टाइडिंग्स के इस अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद करने का अवसर पाकर मुझे अत्यधिक गर्व एवं संतोष की अनुभूति हो रही है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा की गई अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों और गतिविधियों ने देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं उसकी प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। ये प्रयास हमारे साझेदारों, राज्यों, संस्थानों और समुदायों के साथ मिलकर किए गए सामूहिक कार्य का परिणाम है।

इस अवधि के दौरान एनआईडीएम ने लक्षित क्षमता-विकास पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से आपदा-रोधी क्षमता को निरंतर सुदृढ़ किया है, जिनमें आपदा प्रबंधन पर उसके प्रमुख *व्यापक पाठ्यक्रम* भी सम्मिलित रहे। इनमें आपदा-पश्चात् आवश्यकताओं के आकलन एवं समावेशी पुनर्बहाली योजना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन, भूकंपीय सुरक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया। इसके साथ ही शहरी जोखिम प्रबंधन, तथा आकस्मिक एवं हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) से पैदा हुए जोखिमों पर केंद्रित कार्यक्रमों ने उभरती हुई जलवायु-प्रेरित जोखिमों को प्रभावी रूप से संबोधित किया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु भारतीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान नेटवर्क के अंतर्गत की गई सहभागिताओं से शैक्षणिक सहयोग को मजबूती मिली और इससे अनुसंधान-आधारित नीतिगत संवाद को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। शिक्षा क्षेत्र की भूमिका को विशेष महत्व देते हुए एनआईडीएम ने विद्यालय सुरक्षा तथा शिक्षकों और संकाय सदस्यों के क्षमता-विकास से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिससे बच्चों और युवाओं में प्रारंभ से ही सुरक्षा, जागरूकता और ज़िम्मेदारी की भावना विकसित हो सके ।

प्रशिक्षण को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एनआईडीएम ने ई-लर्निंग कार्यक्रमों, iGOT-मिशन *कर्मयोगी* से संबद्ध पाठ्यक्रमों, विषयगत वेबिनारों तथा मिश्रित शिक्षण प्रारूपों के माध्यम से अपने डिजिटल शिक्षण पारितंत्र का विस्तार किया है। इससे राज्यों, संस्थानों और ज़मीनी स्तर के हितधारकों तक व्यापक पहुँच संभव हुई, जिससे निरंतर पेशेवर विकास और ज्ञान का प्रसार सुदृढ़ हुआ है।

13 अक्टूबर 2025 को एनआईडीएम द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर ''हमसे शुरू होती है समुत्थानशीलता'' के संदेश के साथ विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई। ''समुत्थानशील भविष्य, सुरक्षित भारत'' विषय पर आयोजित चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता में दिल्ली-एनसीआर के 200 से अधिक विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिससे युवा वर्ग में जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के माध्यम से व्यक्तिगत ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया। राष्ट्रीय वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन (NATC 2026-27) के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और भविष्य की क्षमता निर्माण की दिशा में पेशेवर संवाद को सशक्त किया गया।

भविष्य में भी एनआईडीएम सशक्त संस्थाओं, जागरूक और सक्षम समुदायों, साक्ष्य-आधारित योजनाओं तथा प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण कार्यों के माध्यम से देश की आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। हम केंद्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर ज्ञान को व्यवहार में बदलने और विकास उपलब्धियों की रक्षा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

एनआईडीएम की ओर से मैं आप सभी को **नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ** देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाला वर्ष हम सबके लिए अधिक सुरक्षित, सशक्त और आपदा-रोधी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मधुप व्यास, भा.प्र.से.

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम दिल्ली परिसर

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 5वां समग्र पाठ्यक्रम, 06-17 अक्टूबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रौद्योगिकी का सक्रिय उपयोग - संस्थागत और स्थानीय जोखिम आकलन को बेहतर बनाने और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, उत्तरदायी संचार और पारदर्शी अनुसंधान के माध्यम से नैतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), सुदूर संवेदन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)/मशीन लर्निंग (ML) मॉडलों का उपयोग करें।
ख)	सभी डीआरआर पहलों में महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समावेशी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियानों के माध्यम से समुदायों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करें।
ग)	समितियाँ बनाकर, जिम्मेदारियाँ सौंपकर, और डीडीएमए और स्थानीय अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय सुनिश्चित करके डीआरआर शासन को संस्थागत बनाएं और तैयारी, जागरूकता और सामुदायिक संपर्क के लिए स्वयंसेवक तैयार करने में एनएसएस, एनसीसी, छात्र क्लबों जैसे युवाओं के नेटवर्क का लाभ उठाएं।
घ)	कम से कम एक ठोस पहल को लागू करके डीआरआर कार्रवाई का नेतृत्व करें, जैसे डीआरआर क्लब का गठन, आपदा प्रबंधन योजना का विकास, या छात्र-संचालित प्रतिरोधक क्षमता परियोजना की शुरुआत और कार्रवाई-आधारित डीआरआर अनुसंधान शुरू करें, जो चिन्हित की गई कमियों को पूरा करता हो, स्थानीय प्राथमिकताओं का समर्थन करता हो, और राष्ट्रीय डीआरआर एजेंडा में योगदान देता हो।

आपदा एवं स्वास्थ्य जोखिमों पर राज्य नोडल अधिकारियों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण: जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य केन्द्रित राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच), 08-10 अक्टूबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	अनुकूलन, आपदा तैयारी और विकास योजना में जलवायु परिवर्तन को एक मुख्य जन स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में माना जाना चाहिए।
ख)	प्रतिक्रियात्मक राहत से आगे बढ़ते हुए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, पूर्वानुमान आधारित निगरानी और अग्रिम शासन व्यवस्था के माध्यम से जलवायु-रोधी स्वास्थ्य प्रणालियों की ओर बढ़ा जाए।
ग)	प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ने वाले स्वास्थ्य इकाई के दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित हो।
घ)	स्वास्थ्य प्रभावों की निगरानी, संवेदनशीलताओं की मैपिंग और अनुकूलनात्मक हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (आईएचआईपी), भारत मौसम विज्ञान विभाग, तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे एकीकृत प्लेटफार्मों को सुदृढ़ किया जाए।
च)	मानसिक स्वास्थ्य जलवायु प्रतिरोधकता के लिए केंद्रीय घटक है, जिसके लिए मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार, पीयर नेटवर्क और समुदाय-आधारित मनोसामाजिक देखभाल को बढ़ावा देना आवश्यक है।
छ)	तैयारी को संस्थागत बनाने, प्रतिक्रिया का समन्वय करने तथा प्रतिरोधकता का निर्माण, निम्न-कार्बन और समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास हेतु स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ संरेखित किया जाए।

नदी घाटियों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ प्रबंधन / हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (जीएलओएफ) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 29-31 अक्टूबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	रिमोट सेंसिंग साक्ष्यों से झीलों के क्षेत्रफल और संख्या में निरंतर वृद्धि का संकेत मिलता है, जिससे अप्रत्याशित झील फटने की घटनाओं को रोकने हेतु सक्रिय निगरानी अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
ख)	केवल झील का आकार ही जोखिम का निर्धारक नहीं होता; मोरेन की संरचना, झील की गहराई, ढलान की अस्थिरता, हिमनद से संपर्क तथा संभावित हिमस्खलन जैसे कारक मिलकर जोखिम को परिभाषित करते हैं।
ग)	चमोली में आए 2021 की बाढ़ से यह स्पष्ट हुआ कि सभी बाढ़ घटनाएँ झील-प्रेरित नहीं होतीं; ढलान के बिखराव तथा बर्फीले चट्टान के हिमस्खलन भी समान स्तर की तबाही का कारण बन सकते हैं।
घ)	जीएलओएफ से जुड़े खतरों को आपदा प्रबंधन योजनाओं, भूमि-उपयोग नियोजन, अवसंरचना अनुमोदनों, जलविद्युत बाँधों की सुरक्षा तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्रों में मुख्य रूप से शामिल करना चाहिए।
च)	जोखिम वाली झीलों की सक्रिय रूप से पहचान करनी चाहिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए तथा शमन, निगरानी और पायलट परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय वैज्ञानिक एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए।
छ)	सिक्किम के अनुभवों से सौर-आधारित पंपिंग द्वारा झील स्तर में कमी और रिटेंशन संरचनाओं जैसे नवोन्मेषी शमन उपायों का क्रियान्वयन का महत्व उजागर हुआ है, साथ ही समन्वय, वित्तपोषण और अनुसंधान की निरंतरता से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता भी रेखांकित हुई है।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 7वां समग्र पाठ्यक्रम, 3-14 नवंबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रतिभागी की जागरूकता, तैयारी और क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, रासायनिक आपदा प्रबंधन पर विशेष सत्र शामिल करने की आवश्यकता है, जिसमें रासायनिक खतरों की पहचान, रोकथाम और प्रतिक्रिया पर जोर दिया जाए, और उच्च जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
ख)	प्रतिभागियों को बुनियादी ग्रह विज्ञान को समझने में मदद करने के लिए सौर मंडल के परिचयात्मक मॉड्यूल का विशेष महत्व है, जिससे वे एक एकीकृत वैज्ञानिक ढांचे के भीतर पर्यावरणीय जोखिमों, जलवायु प्रभावों और आपदा से संबंधित घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।
ग)	आपदा प्रबंधन में न्यायपालिका की भूमिका पर विस्तृत सामग्री तैयार किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि अदालतें और कानूनी संस्थान आपदा शासन को कैसे आकार देते है, जवाबदेही कैसे तय करते हैं और नीति कार्यान्वयन को कैसे प्रभावित करते हैं, इससे प्रतिभागियों को अवगत कराया जा सके।
घ)	प्रतिभागियों को मौजूदा नीतिगत ढांचों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करने और व्यावहारिक और क्रियान्वयन योग्य सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे जानकारी आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा मिलेगा, नीति प्रभावशीलता में सुधार होगा और आपदा प्रबंधन एवं आपदा प्रतिरोधक क्षमता योजना के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा।

आपदा के समय महिलाओं की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6-8 नवंबर 2025, चंडीगढ़

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक लैंगिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो यह समझता हो कि सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारक महिलाओं के लिए जोखिमों को किस प्रकार बढ़ाते हैं। महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का सही आकलन करने और उनके अनुरूप प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए लिंग और आयु के आधार पर पृथक आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ख)	संकट के तुरंत बाद यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य हेतु न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज (MISP) को लागू करना अत्यावश्यक है। इसके लिए स्वास्थ्य, संरक्षण (GBV), लॉजिस्टिक्स और आश्रय क्षेत्रों के बीच मजबूत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे कि सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
ग)	आपदा के दौरान और उसके बाद लैंगिक आधारित हिंसा (GBV) के विभिन्न रूपों जैसे- घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और आर्थिक शोषण का खतरा और प्रसार तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया पीड़िता-केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें गोपनीयता, सुरक्षा पर जोर दिया जाए तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, मनोसामाजिक सहयोग और कानूनी सहायता के लिए स्पष्ट रेफरल मार्ग स्थापित किए जाएँ।
घ)	संकट के समय महत्वपूर्ण यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) सेवाओं, जैसे - सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ (एमटीपी अधिनियम के अनुरूप) और एचआईवी के साथ जी रहे लोगों के लिए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) की निरंतरता को बनाए रखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मातृ एवं नवजात के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मृत्यु दर को कम करने की रणनीतियाँ अपनाना और नवजातों की देखभाल करना आवश्यक है।
च)	यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) योजना, जिसमें लैंगिक आधारित हिंसा (GBV) की रोकथाम शामिल हो, को आपदा-पूर्व तैयारी तथा दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) रणनीतियों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे कि सुदृढ़ प्रणालियों का निर्माण हो सके। इसके साथ ही, प्रतिक्रिया प्रयासों में दिव्यांग महिलाओं और बालिकाओं की पूर्ण पहुँच, सहभागिता और समावेशन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए सभी भौतिक तथा संचार संबंधी बाधाओं को प्रभावी रूप से दूर किया जाए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने पर केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10-14 नवंबर 2025, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण को श्रम और रोज़गार मंत्रालय के सभी विभागों/संस्थानों की दैनिक गतिविधियों, कार्यक्रमों और आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में मुख्यधारा में शामिल किया जाए, जिससे कि आपदा से निपटने के लिए एक संरचित और समन्वित दृष्टिकोण विकसित हो सके ।
ख)	जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव तथा श्रम क्षेत्र में उभरते जोखिमों को पहचानते हुए, कार्यबल पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए श्रम क्षेत्र में उपलब्ध विशिष्ट नीतिगत और वित्तीय उपायों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाए।
ग)	व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों को आपदा जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल के साथ एकीकृत किया जाए, जिससे की औद्योगिक दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं, दोनों से निपटने हेतु एक व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा सके ।
घ)	आपदा जोखिम शमन एवं न्यूनीकरण के लिए प्रकृति-आधारित समाधान तथा जीवन-चक्र दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जिससे पारिस्थितिक रणनीतियों का उपयोग कर दीर्घकालिक आपदा जोखिमों को कम किया जा सके और पर्यावरणीय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सके।
च)	मंत्रालय के कार्यालयों में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (Incident Response System – IRS) को क्रियान्वित किया जाए, जिससे कि संकट की स्थिति में वे समन्वित कमांड केन्द्रों (आपातकालीन संचालन केन्द्र) के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। साथ ही, इसमें समावेशन, सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अंतर्निहित किया जाए।
छ)	क्षमता निर्माण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्राथमिक उपचार, जीवन रक्षक तकनीकों पर आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँ तथा प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार नियमित रूप से मॉक ड्रिल कराई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अधिकारी इन महत्वपूर्ण कौशलों को अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 8वां समग्र पाठ्यक्रम, 17-28 नवंबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	सक्रिय जोखिम प्रबंधन को राहत-केंद्रित प्रतिक्रियाओं का स्थान लेना चाहिए। इसके लिए पूर्वानुमान पर आधारित निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और अग्रिम निर्णय-निर्माण विधि को अपनाया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सकें।
ख)	जोखिम का आकलन समुदायों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए, जिसमें मौसमी कैलेंडर और ट्रांसेक्ट वॉक जैसे भागीदारी वाले तरीकों का उपयोग किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय खतरे, क्षमताएँ और जीवन संबंधी वास्तविकताएँ सीधे तौर पर शमन और तैयारी संबंधी कार्रवाइयों को आकार दें।
ग)	प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया परस्पर-संगत डेटा और डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर करती है। NDMIS, भू-स्थानिक उपकरणों और बहु-चैनल चेतावनी प्रणालियों जैसे प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने से वास्तविक-समय में समन्वय और साक्ष्य-आधारित प्रतिक्रिया में सुधार होगा।
घ)	पुनर्वास योजना में एनडीआरएफ/एसडीआरएफ वित्तपोषण से जुड़ी त्वरित पीडीएनए व्यवस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए। बिल्ड-बैक-बेटर (Build Back Better) सिद्धांतों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि पुनर्वास में किए गए निवेशों को लंबे समय तक चलने वाले मजबूती में बदला जा सके।
च)	संयुक्त अभ्यास, मानकीकृत एसओपी और सामंजस्यपूर्ण उपकरण बहु-एजेंसी समन्वय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। व्यावहारिक सत्रों ने जटिल आपात स्थितियों के दौरान एकीकृत कमान और संचार की आवश्यकताओं को रेखांकित किया।
छ)	आपदा योजनाओं में सुलभता, सहायक प्रौद्योगिकियों और मनो-सामाजिक सहयोग को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, जिससे कि प्रतिक्रिया और पुनर्वास के दौरान उनकी गरिमा, सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित की जा सके।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 9वां समग्र पाठ्यक्रम, 01-12 दिसंबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रतिक्रिया-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्रीय एवं वैश्विक ढांचों के अनुरूप रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता पर विशेष ज़ोर दिया जाए।
ख)	खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता (HRVC) विश्लेषण, संवेदनशीलता मानचित्रण तथा मॉडलिंग जैसे उपकरण साक्ष्य-आधारित योजना, हस्तक्षेपों की प्राथमिकता निर्धारण और क्रियान्वयन योग्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
ग)	आपदाएँ एक साथ सामाजिक क्षेत्रों, बुनियादी ढाँचों, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिसके लिए एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय योजना, क्षति एवं हानि आकलन, और समन्वित रिकवरी रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
घ)	प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ अनिवार्य हैं, जो वैज्ञानिक पूर्वानुमान, संस्थागत समन्वय, CAP-युक्त प्रसार, तकनीकी प्लेटफार्मों और समय पर कार्रवाई के लिए सामुदायिक तैयारी को एकीकृत करते हैं।
च)	जटिल आपात स्थितियों, भीड़ की सुरक्षा और शासन के सभी स्तरों पर त्वरित प्रतिक्रिया के प्रबंधन के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान, क्रियाशील घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, आपातकालीन संचालन केंद्र और शासन के स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
छ)	'बिल्ड बैक बेटर' सिद्धांतों, आपदा पश्चात् आवश्कताओं का आकलन आधारित पुनर्वास योजना प्रकृति-आधारित समाधान और समुदाय की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया, जिससे कि रिकवरी के प्रयास भविष्य के जोखिमों को कम करते हुए सतत विकास को भी सुदृढ़ कर सकें।

पहाड़ी क्षेत्रों और जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधक क्षमता को केन्द्र में रखते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संकाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, 14-18 दिसंबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, हिमनदीय झील फटने से उत्पन्न बाढ़, वनाग्नि, भूकंप और जलवायु-जनित जोखिमों सहित पहाड़ों से संबंधित खतरों की बेहतर समझ हुई।
ख)	महाविद्यालय संकाय की आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु प्रतिरोधक क्षमता को पाठ्यक्रम, अनुसंधान पहलों और संस्थागत योजना में एकीकृत करने की क्षमता में वृद्धि हुई।
ग)	राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (NCMRWF), नोएडा के क्षेत्रीय भ्रमण से प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जल-मौसम विज्ञान पूर्वानुमानों तथा समन्वित प्रतिक्रिया तंत्रों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली।

घ)	HRVCA-आधारित समूह अभ्यासों, सिमुलेशन और आपदा प्रबंधन योजना के विकास के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण अवधारणाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग।
च)	विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के समुदाय-केन्द्रित और मनोसामाजिक आयामों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
छ)	हिमालयी क्षेत्रों में आपदा रोधी और जलवायु-अनुकूलन क्षमता निर्माण में उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

भूकंपीय सुरक्षा पर केन्द्रित शहरी जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
15-19 दिसंबर 2025, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा प्रबंधन अधिनियम (संशोधन), 2025 के अनुसार शहरी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार और अपडेट की जानी चाहिए, जिससे शासन, बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक भागीदारी में कमियों को दूर किया जा सके।
ख)	भूकंपीय जोखिम का आकलन करने और शहरी नियोजन और नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने के लिए राज्य या जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों और शहरी योजनाकारों की क्षमता निर्माण आवश्यक है।
ग)	भूकंपीय क्षेत्र विभाजन मानचित्र में हुए बदलावों ने कई शहरों, विशेष रूप से गैर-इंजीनियर्ड इमारतों, जीवनरक्षक अवसंरचनाओं और अनौपचारिक बस्तियों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है।

घ)	बेसलाइन आकलन, कमियों के विश्लेषण और कार्य योजना के माध्यम से शहरी सुदृढ़ीकरण 2030 (MCR 2030) फ्रेमवर्क शहरों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने लिए व्यवहारिक रोडमैप प्रदान करता है।
च)	संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के सिटी डिज़ास्टर रेज़िलिएंस स्कोरकार्ड (आवश्यकताएँ 1-10) पर आयोजित व्यावहारिक सत्रों ने प्रतिभागियों को स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता की।
छ)	जोखिम आकलन, शमन उपायों तथा पीयर लर्निंग पर व्यावहारिक ज्ञान, 2030 तक सुदृढ़ शहरों के निर्माण की दिशा में सहायक है।

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम दक्षिणी परिसर

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 6वाँ समग्र पाठ्यक्रम, 06-17 अक्टूबर 2025, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	इस बात पर ज़ोर दिया गया कि प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर जैसे कमजोर समूहों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।
ख)	SACHET, CAP और NDEM जैसे उपकरणों के साथ-साथ ड्रोन आधारित एप्लिकेशन को अलर्ट, संसाधन प्रबंधन और वास्तविक समय पर समन्वय के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में प्रदर्शित किया गया।
ग)	बच्चों को केवल कमजोर समूह के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक बाल अधिकार फ्रेमवर्क के अनुरूप, सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में स्थान दिया गया।
घ)	लैंगिक असमानताओं को दूर करने, लैंगिक आधारित हिंसा को रोकने, और आश्रयों, सहायता एवं रिकवरी कार्यक्रमों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का महत्व रेखांकित किया गया।
च)	आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (PDNA) को एक व्यवस्थित उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो अस्थायी राहत से आगे बढ़कर सतत् पुनर्निर्माण और ''बिल्ड बैक बेटर'' की दिशा में मार्गदर्शन करता है।
छ)	समन्वित आपदा प्रतिक्रिया और गलत सूचना को कम करने के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण, क्रॉस सेक्टोरल साझेदारी और जिम्मेदार मीडिया प्रथाओं को आवश्यक बताया गया।

ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण 05-07 नवंबर 2025, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास में निवेश आपदा-प्रतिरोधी और टिकाऊ हों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास योजनाओं और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में एकीकृत करना चाहिए।
ख)	समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन स्थानीय समुदायों को प्रथम उत्तरदाता के रूप में सशक्त बनाता है, स्थानीय ज्ञान, संसाधनों और सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करके प्रभावी और आपदा से स्थायी बचाव के उपाय सुनिश्चित करता है।
ग)	जोखिम, खतरा, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन (HRVCA) जिसमें मौसमी कैलेंडर, ट्रांज़ेक्ट वॉक और सामुदायिक जोखिम मानचित्रण जैसे भागीदारी उपकरणों का उपयोग किया जाता है, समुदायों को आपदा जोखिमों की पहचान करने और उनकी प्राथमिकता तय करने में सक्षम बनाता है।

घ)	बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों के साथ भागीदारीपूर्ण संवेदनशीलता मानचित्रण समावेशी आपदा योजना और लक्षित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करता है।
च)	ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA-बाढ़ बुनियादी ढांचा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) (आपदा-प्रूफ आजीविका), जल जीवन मिशन (सुरक्षित पानी), स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) (बाढ़-रोधी स्वच्छता), और प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) (चक्रवात-रोधी आवास) को ग्राम पंचायत विकास योजना और ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के साथ जोड़ने से संसाधनों का अधिकतम उपयोग और प्रणालीगत प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होता है।

व्यापक स्कूल सुरक्षा और स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 24-28 अक्टूबर 2025, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	स्कूलों में आपदा प्रबंधन को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा एनडीएमए और एसडीएमए/डीडीएमए की व्यवस्थाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय-स्तरीय कार्रवाइयों को प्रारंभिक चेतावनी, प्रतिक्रिया और रिकवरी के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य प्रणालियों से जोड़ा जा सके।
ख)	कुंभकोणम स्कूल आग त्रासदी (2004), डबवाली हरियाणा त्रासदी, और राजस्थान की घटनाओं जैसे पिछले आपदाओं से मिले सबक, जिनमें असुरक्षित स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और गर्मी से संबंधित जोखिम शामिल हैं, यह साफ तौर पर दिखाते हैं कि बुनियादी सुरक्षा नियमों की अनदेखी, भीड़भाड़, खराब निर्माण, और तैयारी की कमी से युवा जिंदगियों का दुखद अंत हो सकता है।

ग)	भारत में स्कूल सुरक्षा को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल न केवल शिक्षा के केन्द्र होते हैं बल्कि आपदाओं के दौरान आश्रय स्थल और सामुदायिक केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं। बच्चे सबसे कमजोर समूहों में से हैं, और असुरक्षित स्कूल भवन, आपातकालीन निकास की कमी, मॉक ड्रिल्स का अभाव और कम जागरूकता आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान स्कूलों को उच्च जोखिम वाले स्थान बना सकते हैं।
घ)	राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति (2016) बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है, जिसमें संरचनात्मक, गैर-संरचनात्मक और मनोसामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, तथा स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी,

	नियमित सुरक्षा ऑडिट, शिक्षकों के क्षमता निर्माण और स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय को अनिवार्य किया गया है।
च)	स्कूलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ रोचक और सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जैसे पाठ्यक्रम एकीकरण, सुरक्षा क्लब, मॉक ड्रिल्स, खेल, प्रतियोगिताएँ, कथा वाचन, क्विज़, अभिनय और बच्चों के नेतृत्व वाली गतिविधियाँ आदि।
छ)	स्कूलों में खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम (HVCR) आकलन एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसके माध्यम से संभावित खतरों, जोखिमग्रस्त समूहों, मौजूदा क्षमताओं और प्राथमिक अंतरालों की पहचान की जा सकती है। यह प्रक्रिया शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ भागीदारीपूर्ण अभ्यासों के माध्यम से प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 10वां समग्र पाठ्यक्रम
08-19 दिसंबर 2025, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	भारत की बहु-आपदा जोखिम संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल पर ज़ोर देना—जिसमें बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, सूखा, CBRN जोखिम और औद्योगिक दुर्घटनाएं शामिल हैं, जिससे कि राज्य, ज़िला और स्थानीय स्तर पर जोखिम-आधारित योजना की ज़रूरत को रेखांकित किया जा सके।
ख)	शहरी बाढ़, लू और सूखे जैसी जलवायु-प्रेरित चरम घटनाओं को बढ़ती चुनौतियों के रूप में उजागर करना, जिनके लिए मज़बूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जोखिम-संवेदनशील शहरी नियोजन और क्षेत्रीय तैयारी की आवश्यकता है, न कि आपदा के बाद राहत पर संकीर्ण ध्यान केन्द्रित करने की।
ग)	आपातकालीन संचालन केंद्र (EOCs), SOPs, संचार प्रणालियों और ज़मीनी समन्वय तंत्र को समय पर और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए मुख्य केन्द्र माना जाना चाहिए, जिसमें अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य प्रणालियां, पुलिस और संबंधित विभाग शामिल हैं।
घ)	NDRF के अधिदेश और परिचालन क्षमताओं का प्रभावी उपयोग, जिसमें बटालियन की तैनाती (10वीं बटालियन के उत्तरदायित्व क्षेत्र/एओआर के संदर्भ सहित), CSSR, MFR, CBRN, बाढ़ एवं पर्वतीय बचाव में विशेष दक्षताएँ, कैनाइन (श्वान) इकाइयाँ, तथा सक्रिय अग्रिम तैनाती को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया संसाधनों के रूप में शामिल किया गया है।

सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार

आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 10-12 अक्टूबर 2025, बेंगलुरु

आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने आपदा से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान, व्यवहार और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान किया। विशेषज्ञ व्याख्यानों, मुख्य भाषणों, पैनल चर्चाओं, संगोष्ठियों तथा शोध-पत्र प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम में आपदाओं के मनोसामाजिक प्रभाव, आघात (ट्रॉमा) देखभाल में प्रगति, जलवायु-जनित मानसिक तनाव, संघर्ष-जनित मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ तथा संवेदनशील समुदायों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया।

इन सत्रों में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हस्तक्षेपों, सामुदायिक समुत्थानशीलता (रेज़िलिएंस), सहभागी शासन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचों में मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता (MHPSS) के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन में टेली-मेंटोरिंग मॉडल, विद्यालय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य तथा विस्तार योग्य ट्रॉमा-संवेदनशील हस्तक्षेपों जैसे नवोन्मेषी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए गए। व्यापक रूप से, इस कार्यक्रम ने विभिन्न विषयों की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता की और आपदा की स्थिति में समावेशी, साक्ष्य-आधारित तथा समुदाय-केन्द्रित मनोसामाजिक सहायता प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया। सम्मेलन में कुल 247 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के बीच सहयोग, आपदा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता के एकीकरण के माध्यम से आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों संस्थान क्षमता निर्माण, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा नीतिगत सहयोग के माध्यम से आपदा प्रबंधन की समस्त प्रक्रियाओं में मनोसामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

तटीय क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र की प्रतिरोधक क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला 16-17 अक्टूबर 2025, दिल्ली

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आठ तटीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से 55 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला ने विद्युत क्षेत्र के पेशेवरों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा तकनीकी विशेषज्ञों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के जोखिमों से निपटने में विद्युत अवसंरचना की प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श हेतु एक सहयोगात्मक मंच प्रदान किया।

चर्चाओं में चरम मौसमीय घटनाओं के प्रति विद्युत प्रणालियों की बढ़ती संवेदनशीलता को रेखांकित किया गया तथा एकीकृत नीतियों, संस्थागत क्षमता निर्माण, और नवोन्मेषी वित्तीय एवं तकनीकी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) वल्लूर, तमिलनाडु तथा कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (CESC), पश्चिम बंगाल से प्रस्तुत केस स्टडीज़ ने चक्रवात से निपटने की मजबूत तैयारी, सुदृढ़ अवसंरचना डिज़ाइन तथा प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों जैसी व्यावहारिक समुत्थानशील पहलों को उजागर किया।

कार्यशाला का समापन विद्युत क्षेत्र की प्रतिरोधक क्षमता पर संक्षेप में नीति विकसित करने, नियमित क्षमता-वर्धन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, तथा विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMAs सहित प्रमुख संस्थानों के बीच समन्वय

सुदृढ़ करने की सहमति के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने विद्युत क्षेत्र की नीतियों और निवेश ढाँचों में समुत्थानशीलता को मुख्यधारा में लाने, राज्य-स्तरीय सफल मॉडलों का विस्तार करने, तथा नवाचार और जानकारियों को एक दूसरे से साझा करने को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। व्यापक तौर पर, कार्यशाला ने भारत के तटीय क्षेत्रों के लिए जलवायु रोधी, विश्वसनीय और सतत विद्युत क्षेत्र के विकास की दिशा में सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रमाणित किया।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) के तहत दो-चरणों में मूल्यांकन पर अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (IMCT) और मल्टी-सेक्टोरल टीम (MST) के सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यशाला 24 अक्टूबर 2025, दिल्ली

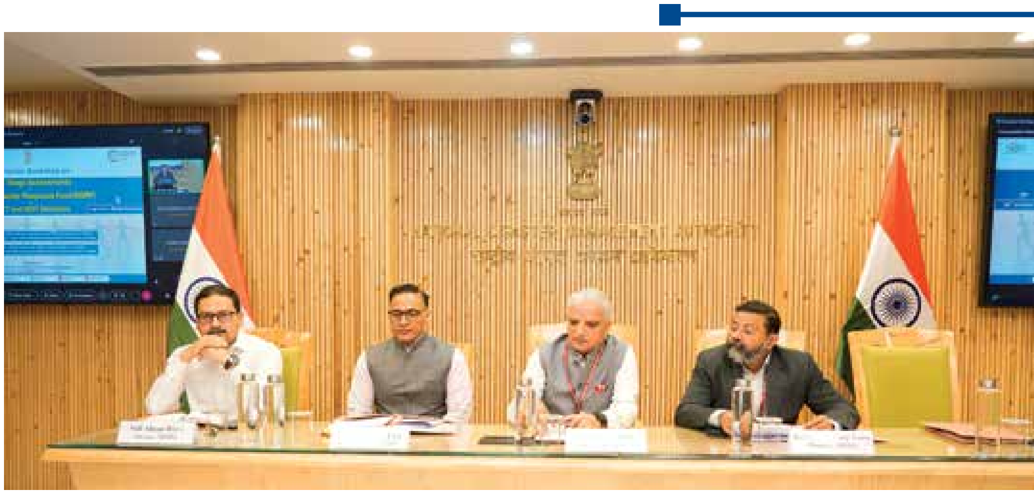

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) के अंतर्गत द्वि-चरणीय आकलन पर अभिमुखीकरण कार्यशाला, जो 24 अक्टूबर 2025 को एनडीएमए भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (IMCT) एवं मल्टी-सेक्टोरल टीम (MST) के सदस्यों की संरचित आपदा-पश्चात् आकलन करने की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला में प्रतिभागियों को द्वि-चरणीय आकलन प्रक्रिया से परिचित कराया गया, जिसमें प्रथम चरण में त्वरित प्रतिक्रिया एवं राहत तथा द्वितीय चरण में आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन PDNA ढाँचे के अंतर्गत पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण को शामिल किया गया।

PDNA पद्धति, पुनर्बहाली योजना, सहायता अनुशंसाओं तथा स्फीयर स्टैंडर्ड्स और त्वरित बहु-क्षेत्रीय आकलन उपकरणों जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर विशेषज्ञ सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों की साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तथा "Build Back Better" दृष्टिकोण की समझ को सुदृढ़ किया गया। इस कार्यशाला ने NDRF के अंतर्गत आपदा आकलन एवं पुनर्बहाली प्रस्तावों की गुणवत्ता, सटीकता और गति को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक एवं नीति आधारित दिशा दी।

इन सत्रों के दौरान सटीक, पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारित क्षति और नुकसान के आकलन के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), सुदूर संवेदन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI-आधारित प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व को रेखांकित किया गया। इसमें समन्वय को सुदृढ़ करने और दोहराव से बचने के लिए मानकीकृत डेटा प्रारूप, डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफार्म तथा जियो-टैग की गई जानकारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस उपयोगी वर्कशॉप का मकसद आपदा आकलन में बेहतर दक्षता और तालमेल के लिए क्षमता निर्माण, मॉक एक्सरसाइज और मंत्रालयों के बीच सहयोग को मज़बूत करना था।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन (SBC) पर तृतीय क्षेत्रीय कार्यशाला, 27-28 अक्टूबर 2025, दिल्ली

NIDM और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) द्वारा तीन-भाग की राष्ट्रीय श्रृंखला के एक भाग के रूप में संयुक्त रूप से आयोजित इस वर्कशॉप में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 23 अधिकारियों ने भाग लिया। इसका मकसद SDMA और अन्य प्रमुख हितधारकों से जुड़े सरकारी अधिकारियों की क्षमता को मज़बूत करना था, जिससे कि आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन सिद्धांतों को प्रभावी रूप से शामिल किया जा सके।

इस कार्यशाला में व्यावहारिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केस स्टडीज़ और ग्रुप एक्सरसाइज़ सहित इंटरैक्टिव और व्यावहारिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। एक प्रमुख आकर्षण SBC टूलकिट का परिचय रहा, जिसमें प्रभावी सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए संचार सामग्री और व्यावहारिक संसाधन शामिल थे। इसके अतिरिक्त, असम से प्राप्त SBC क्रियान्वयन अनुभव भी प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया।

जलवायु आकलन रिपोर्ट के निष्कर्षों पर परामर्शात्मक कार्यशाला 22 दिसंबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2025 को अपने दिल्ली परिसर में ''जलवायु आकलन रिपोर्ट के निष्कर्षों पर परामर्शात्मक कार्यशाला'' का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला ''राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों का विकास'' परियोजना के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बदलते जलवायु जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU), स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), एनआईटी वारंगल, आईआईटी बॉम्बे, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) सहित विभिन्न संस्थानों से जलवायु वैज्ञानिकों, अवसंरचना विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं एवं प्रैक्टिसनर्स ने भाग लिया।

प्रो. विमलेश पंत, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज़, आईआईटी दिल्ली, ने ''भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा एवं तापमान का डाउनस्केलिंग'' विषय पर एक तकनीकी प्रस्तुति दी। इसमें उन्होंने 2030 से 2090 तक अलग-अलग भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में 2000 किलोमीटर में फैले 30 चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर भविष्य के जलवायु अनुमानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 10 वैश्विक स्तर पर माने जाने वाले मॉडलों के समूह का उपयोग करके तैयार किए गए आउटपुट को पेश किया, जिनका भारतीय उपमहाद्वीप पर बेहतर प्रतिनिधित्व है।

इससे मिली जानकारी वैज्ञानिक सबूतों को व्यावहारिक समाधानों में बदलने में मदद करेगी, जिससे जलवायु रोधी हाईवे बनाने में सहायता मिलेगी और जो जीवन की सुरक्षा, निवेश की रक्षा तथा भारत की दीर्घकालिक अवसंरचना को निरंतर सुदृढ़ करने में सहायक होंगे।

अन्य क्रियाकलाप

CPR पर जागरूकता कार्यक्रम, 17 अक्टूबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 16वीं बटालियन के सहयोग से 17 अक्टूबर 2025 को एनआईडीएम रोहिणी परिसर में अपने कर्मचारियों के लिए ''CPR पर जागरूकता कार्यक्रम'' का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य जान बचाने की बेसिक तकनीकों की समझ को बढ़ाना और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान समय पर रिस्पॉन्स देने के महत्व को रेखांकित करना था।

सत्र की शुरुआत सुरक्षा शपथ के साथ हुई, जिसके उपरांत कर्नल मनोरम यादव (एसएम), संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम ने उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं संस्थान के सदस्यों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि CPR कब और कैसे दिया जाना चाहिए, इसकी सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में NDRF की 16वीं बटालियन की टीम द्वारा इस विषय की बारीकियों से अवगत कराया गया एवं व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सत्र के दौरान बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) और चेन ऑफ सर्वाइवल को समझना, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ और हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानकारी, सीपीआर तकनीकों का चरणबद्ध प्रशिक्षण, CPR सीक्वेंस, सफलता के संकेत तथा सामान्य त्रुटियाँ जिनसे बचना चाहिए सहित तमाम पहलुओं को विस्तार से समझाया गया।

अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) 2025, 19 अक्टूबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) 2025 के उपलक्ष्य में ''समुत्थानशील भविष्य, सुरक्षित भारत'' थीम पर 19 अक्टूबर 2025 को चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में दिल्ली-एनसीआर के प्रतिष्ठित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कल्पनाशक्ति को कला और शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इन प्रतियोगिता के विजेताओं को गणमान्य अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालय तथा विभिन्न महाविद्यालयों के कुल 184 छात्रों और 55 शिक्षकों ने भाग लिया। आयोजन में श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, श्रीकृष्ण कुमार, भा.प्र.से, सीईओ, डीडीएमए, श्री कुमार अभिषेक, भा.प्र.से, जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर दिल्ली, सुश्री ऋषिता गुप्ता, भा.प्र.से, उपायुक्त, एमसीडी रोहिणी तथा श्री प्रतीक जराड, एसडीएम, नरेला की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. पंकज कुमार, सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम द्वारा किया गया।

युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने हेतु एनआईडीएम जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों का दक्षिणी परिसर का दौरा - 23 अक्टूबर, 2025, आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के दक्षिणी परिसर ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत 23 अक्टूबर 2025 को विकास विद्या वनम स्कूल के उत्साही विद्यार्थियों के एक समूह की मेज़बानी की। इस भ्रमण का उद्देश्य युवाओं को आपदा तैयारी एवं प्रतिरोधक क्षमता निर्माण के महत्व से परिचित कराना था।

इन छात्रों को एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर का भ्रमण कराया गया, जहाँ उन्होंने संस्थान की विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया और आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने में एनआईडीएम की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, छात्रों ने भारतीय सेना द्वारा मानवीय सहायता प्रयासों पर आधारित एक प्रेरक वीडियो भी देखा तथा कर्नल पी. एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम दक्षिणी परिसर के साथ एक रोचक संवाद सत्र में भाग लिया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान सत्यनिष्ठा की शपथ, 27 अक्टूबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सदस्यों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत 27 अक्टूबर 2025 को सत्यनिष्ठा की शपथ ली, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। यह शपथ श्री रणदीप राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम द्वारा श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम और कर्नल मनोरम यादव, एसएम, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम की गरिमामयी उपस्थिति में दिलाई गई। इस शपथ समारोह में एनआईडीएम के संकाय सदस्यों सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण के उच्चतम मापदंड को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यक्रम के दौरान, श्री रणदीप राणा ने सतर्कता तंत्र पर एक प्रस्तुति पेश की, जिसमें संस्थागत कार्यप्रणाली में आंतरिक पारदर्शिता प्रणालियों, निवारक सतर्कता और नैतिक निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया गया। इस अवसर पर एनआईडीएम के सदस्यों ने यह स्पष्ट किया कि सत्यनिष्ठा सिर्फ एक शपथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जिस पर विश्वास और सुशासन टिका हुआ है।

आग के जोखिम को कम करने पर जागरूकता कार्यशाला, 18 अक्टूबर 2025, दिल्ली

एनआईडीएम दिल्ली परिसर ने आग जोखिम न्यूनीकरण, कार्यस्थल पर अग्नि सुरक्षा एवं बचाव उपायों पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य संस्थाओं में सुरक्षा जागरूकता, तत्परता और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना था। श्री रणदीप राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम और डॉ. आमिर अली खान, प्रमुख, आरआईडी, एनआईडीएम ने जाने-माने विशेषज्ञों श्री आर.सी. शर्मा (पूर्व निदेशक, डीएफएस) और श्री डी.बी. मुखर्जी (उप प्रमुख अग्निशमन अधिकारी, डीएफएस) का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने अपनी गहरी विशेषज्ञता से वर्कशॉप को और भी बेहतर बनाया।

श्री आर.सी. शर्मा ने कोविड-19 काल की अग्नि सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तविक जीवन की घटनाओं को साझा किया। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में ध्यान रखने योग्य कुछ अहम सुरक्षा टिप्स भी दिए। श्री डी.बी. मुखर्जी ने कार्यस्थल में अग्नि रोकथाम, आवश्यक सुरक्षा उपाय और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रथाओं पर एक आकर्षक सत्र का संचालन किया। इस

अवसर पर एनआईडीएम के अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव और अभ्यास किया।

संभावनाओं का विस्तार : भविष्य के सहयोग पर यूएनडीआरआर-एनआईडीएम संवाद 27 नवंबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के साथ संभावित सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए आए यूएनडीआरआर के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख श्री मार्को टोस्कानो-रिवाल्टा का एनआईडीएम में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, तथा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री मार्को के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण में साझेदारी की संभावनाओं पर रचनात्मक चर्चा की।

यह बातचीत उन क्षेत्रों पर केन्द्रित थी जहाँ मिलकर किए गए प्रयास प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत कर सकते हैं, संस्थागत क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, और बदलते जोखिमों से निपटने के लिए एक समावेशी फ्रेमवर्क के विकास में सहायता कर सकते हैं। इस दौरे से एक सार्थक सहयोग को आकार देने में आपसी दिलचस्पी दिखी जो DRR में भारत के नेतृत्व को आगे बढ़ा सकता है और वैश्विक आपदा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण के प्रयासों में सार्थक योगदान दे सकता है।

दक्षिण मध्य रेलवे के सिविल डिफेंस कर्मियों का एनआईडीएम दक्षिण परिसर का दौरा
18 नवंबर 2025, आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के दक्षिणी परिसर ने दक्षिण मध्य रेलवे के सिविल डिफेंस कर्मियों के लिए परिसर भ्रमण का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य उन्हें आपदा प्रबंधन के बुनियादी बातों और व्यावहारिक ज्ञान से अवगत कराना था।

भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन की मूल बातें, जैसे आपदाओं के प्रकार, तैयारी के उपाय और प्रतिक्रिया तंत्रों के बारे में अवगत कराया गया। आपातकालीन स्थितियों के दौरान सुरक्षा और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, भीड़ प्रबंधन का अभ्यास भी कराया गया, जिससे प्रतिभागियों को बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने, सुव्यवस्थित आवाजाही बनाए रखने, घबराहट रोकने और आपातकालीन स्थितियों एवं बड़े आयोजनों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव दिया गया।

शिक्षक सम्मेलन- आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025
28 नवंबर 2025, देहरादून

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 28 नवंबर 2025 को ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून में ''शिक्षा के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का मुख्यधारा में समावेशन'' विषय पर शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया। यह कार्यक्रम आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025 के तहत हुआ, जिसका आयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) द्वारा किया गया।

सत्र की अध्यक्षता प्रो. के. के. पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की ने की, और इस अवसर पर प्रो. नर्पिंदर सिंह, कुलपति, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय; डॉ. शकील ए. रोमशू, कुलपति, IUST कश्मीर; डॉ. प्रदीप कुमार रामन्चरला, निदेशक, CSIR-CBRI; प्रो. (डॉ.) वीरेंद्र कुमार पॉल, निदेशक, SPA दिल्ली; प्रो. राजीव मोहन पंत, कुलपति, असम विश्वविद्यालय और डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम उपस्थित रहे।

एनआईडीएम-आईयूआईएनडीआरआर द्वारा आयोजित शैक्षणिक अनुसंधान परिषद (ARC) की बैठक
01 दिसंबर 2025, दिल्ली

एनआईडीएम-आईयूआईएनडीआरआर के द्वारा 1 दिसंबर 2025 को दिल्ली परिसर में श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम और शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के चेयरपर्सन की अध्यक्षता में शैक्षणिक अनुसंधान परिषद् (ARC) की बैठक आयोजित की गई, जिसका लक्ष्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक सुदृढ़ और अनुसंधान-आधारित भविष्य का निर्माण करना था। इस बैठक में डॉ. राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय, प्रो. दीवान एस. रावत, कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय सहित अन्य जाने-माने शिक्षाविद् और विशेषज्ञ उपस्थित थे।

मीटिंग में तीन मुख्य घटकों के लिए रिसर्च क्षेत्रों, विषयों और थीम पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें एनआईडीएम डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम, रिसर्च प्रोजेक्ट/अध्ययन, और वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए बेस्ट थीसिस रैंकिंग फ्रेमवर्क शामिल था।

एनआईडीएम और इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, 08 दिसंबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया (ITPI) के बीच 08 दिसंबर 2025 को एनआईडीएम, दिल्ली परिसर में समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया गया। इस सहयोग का उद्देश्य शहरी प्रतिरोधक क्षमता, स्थायी योजना और क्षमता निर्माण के प्रयासों को मजबूत करना है।

श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम; श्री प्रदीप कपूर, अध्यक्ष, ITPI; श्री नरेंद्र के पटेल, संरक्षक, ITPI; कर्नल मनोरम यादव, एसएम, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम; और श्री रणदीप राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

नाइजीरिया संघीय गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल का एनआईडीएम दौरा 17 दिसंबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 17 दिसंबर 2025 को नाइजीरिया संघीय गणराज्य की विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया, जिसमें दो माननीय सांसद और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। यह अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विनिमय शहरी प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलन योग्य सामाजिक सुरक्षा पर आधारित था, जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ''नाइजीरिया कम्युनिटी एक्शन फॉर रेजिलिएंस एंड इकॉनोमिक स्टिमुलस (NG-CARES)'' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। यह यात्रा ''अनुकूलन योग्य सामाजिक सुरक्षा प्रणाली'' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यात्रा के रूप में आयोजित की गई, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR), दिल्ली शाखा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था।

इस अवसर पर श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम; कर्नल मनोरम यादव, एसएम, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम; श्री रणदीप राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम सहित NIRDPR एवं एनआईडीएम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के विद्यार्थियों का एनआईडीएम दौरा, 18 दिसंबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को 18 दिसंबर, 2025 को भारत की ग्लोबल स्टडी ट्रिप के दौरान कैलिफ़ोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के एमबीए छात्रों का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। छात्रों ने एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, संकाय सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। चर्चा जलवायु समुत्थानशीलता, जन स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और उत्पादकता जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित थी।

इस बातचीत से छात्रों को जलवायु-प्रेरित जोखिमों के प्रबंधन, आपदा तैयारियों को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के भारत के दृष्टिकोण के बारे में पहली बार जानकारी मिली। इस दौरे ने सार्थक विचारों के आदान-प्रदान का अवसर दिया और इस समझ को मजबूत किया कि जलवायु और आपदा प्रतिरोधक क्षमता का भविष्य सशक्त युवाओं द्वारा आकार दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर मॉडल पाठ्यक्रम यूजीसी को सौंपा गया, 23 दिसंबर 2025, दिल्ली

उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा एआईसीटीई के सहयोग से नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन (DRR&M) पर मॉडल पाठ्यक्रम विकसित किया है।

श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम और डॉ. प्रीति सोनी, वरिष्ठ सलाहकार, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम के द्वारा यह मॉडल पाठ्यक्रम 23 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सौंप दिया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW) के विद्यार्थियों का एनआईडीएम दौरा 23 दिसंबर 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू), दिल्ली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे 10 रेज़िडेंट डॉक्टरों के एक समूह ने 23 दिसंबर 2025 को अपराह्न 2:30 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) का दौरा किया। इस अवसर पर श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर ने संवाद सत्र के दौरान प्रतिभागियों को एनआईडीएम एवं उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में डॉ. कुमार अभिनय, डॉ. विशाल, श्री सत्यम तथा सुश्री विनीता, शोध सहयोगी, एनआईडीएम भी उपस्थित रहे।

संवाद सत्र के दौरान आगंतुक डॉक्टरों ने संस्थान के अधिदेश, अस्पतालों में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना, आपदा के रूप में प्रदूषण तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005/2025 से संबंधित विभिन्न प्रश्न उठाए, जिनका संतोषजनक उत्तर दिया गया। इस दौरे के समापन पर विद्यार्थियों ने एनआईडीएम द्वारा किए जा रहे क्षमता निर्माण प्रयासों तथा भ्रमण के दौरान प्रदान की गई आतिथ्य की सराहना की।

परियोजना के क्रियाकलाप

जलवायु अनुकूल सुदृढ़ राजमार्गों पर राष्ट्रीय सम्मेलन (CARH) 2025
30-31 अक्टूबर 2025, दिल्ली

जलवायु अनुकूल सुदृढ़ राजमार्गों पर राष्ट्रीय सम्मेलन (CARH) 2025 का आयोजन 30-31 अक्टूबर 2025 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सहयोग से "राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों का विकास" शीर्षक परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया गया।। इस सम्मेलन ने राजमार्ग क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के वैज्ञानिक, तकनीकी, नीतिगत एवं संस्थागत आयामों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। दो दिवसीय इस सम्मेलन में पूर्ण सत्र, गोलमेज चर्चाएँ, टेबल-टॉप अभ्यास तथा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सम्मेलन के उद्देश्यों के अनुरूप थीं।

उद्घाटन सत्र के दौरान श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, NIDM, डॉ. एस. एल. स्वामी, अध्यक्ष, ICE (I) तथा प्रो. प्रेम कृष्णा (सेवानिवृत), आईआईटी रुड़की के विचारों ने NIDM, MoRTH, NDMA, NHAI, NHIDCL, IMD, ISRO, शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकारों एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच मल्टी-सेक्टोरल समन्वय की आवश्यकता को सामूहिक रूप से रेखांकित किया। तकनीकी सत्रों के दौरान सम्मेलन में जलवायु-रोधी राजमार्गों के विभिन्न आयामों की समीक्षा की गई। बहु-आपदा जोखिम आकलन पर हुई चर्चाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव जैसे विभिन्न चरणों में भू-स्थानिक उपकरणों, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, ढलान स्थिरता विश्लेषण, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग और जलवायु अनुमानों को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया गया।

सम्मेलन का समापन श्री मनीष भारद्वाज, सचिव, NDMA के संबोधन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि राजमार्ग विकसित भारत (Viksit Bharat) का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इस दिशा में NHAI की भूमिका शोध एवं अंतर-क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हितधारकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाने की NIDM की पहल की सराहना की। वहीं श्री कृष्ण वत्स, माननीय सदस्य, NDMA ने अपने वक्तव्य में कहा कि परिवहन अवसंरचनाएँ अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOFs) एवं हिमस्खलन जैसी आपदाओं के बढ़ते जोखिमों के कारण अधिक संवेदनशील होती जा रही हैं।

सूखा नियमावली संशोधन-2020 पर क्षेत्रीय (उत्तर) हितधारक कार्यशाला
27 नवंबर 2025, लुधियाना

कृषि में सूखा, शीत लहर, ओलावृष्टि एवं कीट आक्रमण के बढ़ते प्रभावों पर किसानों के दृष्टिकोण को संकलित करने हेतु 27 नवंबर 2025 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में किसान परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कृषि मौसम विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRPAM) के तत्वावधान में आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि-मौसम वैज्ञानिकों, विस्तार कर्मियों तथा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने भाग लिया और जलवायु जोखिम, तैयारी, परामर्श सेवाओं, बीमा तथा संस्थागत प्रतिक्रिया तंत्रों पर विचार-विमर्श किया।

कार्यशाला में चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनका फोकस सूखा, शीत लहर, ओलावृष्टि एवं कीट आक्रमण रहा। इन सत्रों की अध्यक्षता श्री शिव नारायण सिद्ध, समन्वयक एवं परियोजना निदेशक, एनआईडीएम तथा डॉ. एस.के. बल, परियोजना समन्वयक (AICRPAM), केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA) ने की। सत्रों में प्रतिष्ठित वक्ताओं एवं प्रतिभागियों ने शिरकत की, जिनमें डॉ. ए.के. नायक, उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR); डॉ. विनोद कुमार सिंह,

निदेशक, CRIDA; डॉ. के. वेंकटेश्वर राव, प्रमुख, संसाधन प्रबंधन, CRIDA; तथा डॉ. ए.वी.एम. सुब्बा राव, प्रधान वैज्ञानिक, CRIDA शामिल थे।

चर्चाओं में इस बात पर बल दिया गया कि सूखा एवं शीत लहर के आकलन में केवल वर्षा एवं तापमान आधारित सीमाओं से आगे बढ़ते हुए प्रभाव-आधारित आकलन को अपनाने की आवश्यकता है, साथ ही अत्यधिक स्थानीयकृत ओलावृष्टि एवं मौसम-संबंधित कीट जोखिमों के लिए नाउकास्टिंग एवं परामर्श सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए। किसानों ने कार्रवाई-उन्मुख प्रारंभिक चेतावनी, क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना प्रसार, बीमा तक बेहतर पहुँच, प्रौद्योगिकी-युक्त क्षति आकलन तथा विशेष रूप से समय पर सिंचाई सहायता के लिए मजबूत संस्थागत समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यशाला का समापन पारंपरिक ज्ञान के एकीकरण, सूखा घोषणा मानदंडों की पुनर्समीक्षा तथा कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बेहतर सामंजस्य पर सहमति के साथ हुआ।

सूखा नियमावली संशोधन-2020 पर क्षेत्रीय (दक्षिण) हितधारक कार्यशाला 23 दिसंबर 2025, आंध्र प्रदेश

सूखा मैनुअल संशोधन 2020 की चल रही प्रक्रिया और ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला और कीट हमले के लिए दिशा-निर्देश बनाने के हिस्से के रूप में, 23 दिसंबर 2025 को एनआईडीएम दक्षिणी परिसर, विजयवाड़ा में एक क्षेत्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पूर्व में आयोजित इसी तरह की क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के क्रम में आयोजित की गई थी, जिनमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में आयोजित किसान परामर्श कार्यशाला भी शामिल थी, और इसका उद्देश्य दक्षिण भारत से क्षेत्र-विशिष्ट जानकारी एकत्रित करना था।

इस कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के प्रगतिशील किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि मौसम विज्ञानी, एक्सटेंशन पर्सनल, राज्य अधिकारी और नीति विशेषज्ञ सम्मिलित हुए। इसका फोकस जमीनी स्तर के अनुभवों को डॉक्यूमेंट करने, मौजूदा फ्रेमवर्क में कमियों की पहचान करने और कृषि और संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली जलवायु चरम सीमाओं के लिए तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी, प्रतिक्रिया और रिकवरी तंत्र को मजबूत करने पर था। प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में कर्नल पी. एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम (साउथ कैंपस); श्री अर्नब ढाकी, उप सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; डॉ. विनोद कुमार सिंह, निदेशक, सीआरआईडीए; डॉ. के. वेंकटेश्वर राव, प्रमुख, संसाधन प्रबंधन, CRIDA, श्री शिव नारायण सिद्ध, समन्वयक और परियोजना निदेशक, एनआईडीएम और श्री मनजीत सिंह, सह-पीआई और सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम शामिल थे।

क्षेत्रीय हितधारक कार्यशाला में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कृषि को प्रभावित करने वाली जलवायु चरम सीमाएँ जटिल, बार-बार होने वाली और आपस में जुड़ी हुई हैं। किसानों को सूखा, लू, कीटों के प्रकोप और ओलावृष्टि जैसी चरम मौसमी घटनाओं सामना करना पड़ता है। चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि संशोधित मैनुअल और दिशा-निर्देश किसान-केन्द्रित, क्षेत्र-विशेष और जमीन पर लागू करने योग्य होने चाहिए। कार्यशाला के दौरान प्राप्त इनपुट कृषि आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु प्रतिरोधक क्षमता के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

विषयगत दृष्टिकोण

प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के तौर पर पंचायतें : भारत में समुदाय-केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण

डॉ. सुषमा गुलेरिया
सहायक प्रोफेसर

73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को 29 विकासात्मक विषयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें से अनेक सीधे तौर पर आपदा समुत्थानशीलता से जुड़े हैं। अतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण जमीनी स्तर के शासन का एक अभिन्न अंग है, न कि केवल एक स्वतंत्र आपातकालीन कार्य। इसी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। इसके पश्चात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने ग्राम आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करने तथा पंचायत प्रतिनिधियों के लिए देशव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इस पहल को मजबूत समर्थन दिया।

2025 में, एनआईडीएम ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर पंचायत ओरिएंटेशन शुरू किए, जिन्हें क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया जाएगा, जिससे कि वित्त वर्ष 2026-27 में जमीनी स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संस्थागत बनाया जा सके। इस दृष्टिकोण को और मजबूत करते हुए, सरकार ने 20 राज्यों और 81 आपदा-प्रवण जिलों को कवर करते हुए, पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक राष्ट्रीय परियोजना के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के तहत 503 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह परियोजना संस्थागत मजबूती, विकास योजनाओं का आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ समायोजन, क्षमता निर्माण,

भारत के आपदा अनुभव में, औपचारिक आपातकालीन एजेंसियों के पहुँचने से पहले लगभग हमेशा प्रथम प्रतिक्रिया समुदाय के भीतर से ही आती है। संकट के प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण घंटों में जब चेतावनी प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं और औपचारिक राहत बलों को पहुँचने में समय लगता है पंचायतें और स्थानीय समुदाय तत्काल बचाव, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, सुरक्षित स्थानों पर निकासी तथा भावनात्मक संबल प्रदान करते हैं। पंचायतों की वास्तविक शक्ति किसी विशेष तकनीकी प्रशिक्षण में नहीं, बल्कि उनके स्थानीय ज्ञान, सामाजिक विश्वास और भौगोलिक निकटता में निहित है। वे जानते हैं कि कौन-से क्षेत्र सबसे पहले जलमग्न होते हैं, कौन-से परिवार सबसे अधिक संवेदनशील हैं और कहाँ तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। इस प्रकार पंचायतें अक्सर प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता होती हैं और संकट समाप्त होने तक अंतिम रूप से सक्रिय रहती हैं। इसके बावजूद, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ढाँचों में उनकी भूमिका को अभी भी पर्याप्त मान्यता नहीं मिल पाई है।

और मॉडल आपदा-रोधी ग्राम पंचायतों के निर्माण पर केन्द्रित है।

आपदा-रोधी भारत के निर्माण के लिए एक बॉटम-अप दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पंचायतों को योजना, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के केन्द्र में रखता है। स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने से सामुदायिक ज्ञान और विश्वास स्थायी मजबूती में बदल जाता है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रभावी, समावेशी और स्थायी बनाता है। अगर पंचायतें सबसे पहले मदद करती हैं और सबसे आखिर में जाती हैं, तो उन्हें आपदा योजना और जोखिम कम करने की रणनीतियों में भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। नीति एकीकरण, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता के ज़रिए पंचायतों को मज़बूत बनाना सिर्फ़ विकेंद्रीकरण नहीं है, यह रणनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। आपदा-रोधी भारत सिर्फ़ बॉटम-अप गवर्नेंस अप्रोच से ही हासिल किया जा सकता है, जहाँ सशक्त पंचायतें स्थानीय ज्ञान, सामाजिक विश्वास और विकास योजनाओं को स्थायी आपदा प्रतिरोधकता में बदल देती हैं।

भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण : प्रतिरोधक क्षमता की तरफ प्रतिमान विस्थापन

डॉ. रविन्द्र सिंह
वरिष्ठ परामर्शदाता, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)

प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाएँ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर प्रभावित कर रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि, अवसंरचनाओं को क्षति तथा कर राजस्व में कमी और पुनर्निर्माण लागत के कारण गंभीर वित्तीय दबाव उत्पन्न होता है। जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि, अत्यधिक गर्म दिनों और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के रूप में हो रहा है, जिससे मजबूत वित्तीय संरक्षण की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में इस दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पारंपरिक राहत-केन्द्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एकीकृत आपदा जोखिम वित्तपोषण (Disaster Risk Financing–DRF) के माध्यम से सक्रिय, जोखिम-न्यूनीकरण रणनीति अपनाई जा रही है।

आपदा जोखिम वित्तपोषण का उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना है, जिसके लिए निर्णय लेने में सहायक मात्रात्मक आर्थिक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से, जी-20 तथा विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने ऐसी रणनीतियों का समर्थन किया है, जो आपदा एवं जलवायु जोखिम को व्यापक वित्तीय संरक्षण ढाँचों में एकीकृत करती हैं।

इन रणनीतियों के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- जोखिम आकलन एवं मॉडलिंग : वित्तीय योजना को सूचित करने हेतु खतरों, जोखिम-प्रदर्शन (एक्सपोज़र) तथा संवेदनशीलताओं का मात्रात्मक आकलन।
- जोखिम हस्तांतरण उपकरण : वित्तीय नुकसान के प्रबंधन हेतु कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड तथा पैरामीट्रिक बीमा जैसे साधनों का उपयोग।
- सार्वजनिक-निजी सहयोग : आपदा बीमा बाज़ारों के सहयोग के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, भारत ने 2021-2026 की अवधि और उसके बाद के वर्षों के लिए एक नया वित्तीय ढांचा बनाया है, जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए 28,011 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹2.28 लाख करोड़) का फंड तय किया गया है।

स्तर	जोखिम प्रबंधन कोष (प्रतिक्रिया + शमन)	घटक कोष
राष्ट्रीय	राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ)	राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (शमन) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (प्रतिक्रिया)
राज्य	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ)	राज्य आपदा शमन कोष (शमन) एवं राज्य आपदा मोचन बल (प्रतिक्रिया)

एनडीआरएमएफ और एसडीआरएमएफ का आवंटन रणनीतिक रूप से बांटा गया है, जिसमें रिस्पॉन्स और रिलीफ को 40%, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन को 30%, मिटिगेशन को 20%, और तैयारी/क्षमता निर्माण को 10% राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मिलता है।

भारत जाने-माने इंटरनेशनल आपदा जोखिम पूल से सीख ले सकता है जो किफ़ायती हैं और तत्काल लिक्विडिटी प्रदान करते हैं:

- प्राकृतिक आपदाओं के लिए फंड - FONDEN, मेक्सिको (1996): एक बहुवर्षीय आरक्षित कोष, जो सार्वजनिक अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए वित्तपोषण करता है तथा संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पैरामीट्रिक कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड का उपयोग करता है।
- तुर्की आपदा बीमा पूल - TCIP, तुर्की (1999): आवासीय संपत्तियों के लिए अनिवार्य भूकंप बीमा प्रदान करता है, और वार्षिक रूप से कवरेज का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए निर्माण मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है।
- यूरोपीय यूनियन सॉलिडेरिटी फंड (2002) सदस्य देशों को बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया है। यह महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और आपातकालीन सेवाओं के लिए गैर-बीमा योग्य नुकसान को कवर करता है। फंडिंग ऑटोमैटिक नहीं है, इसके लिए दस हफ़्तों के भीतर विशिष्ट नुकसान की सीमा और आवेदन की आवश्यकता होती है।
- कैरेबियन आपदा जोखिम बीमा सुविधा - CCRIF (2007): एक पारस्परिक बीमा कंपनी है, जो कैरेबियन और मध्य अमेरिकी सरकारों को किफायती, अल्पकालिक तरलता प्रदान करती है। यह तूफान और भूकंप के जोखिमों के लिए दो हफ़्तों के भीतर तुरंत नकद भुगतान की पेशकश करने के लिए पूल्ड रिज़र्व और पुनर्बीमा का उपयोग करती है।
- प्रशांत आपदा जोखिम वित्तपोषण एवं बीमा - PDRFI (2013): प्रशांत द्वीपसमूह की अर्थव्यवस्थाओं को सलाहकार सेवाएँ और पायलट कैटास्ट्रॉफी जोखिम हस्तांतरण कार्यक्रम प्रदान करता है। भूकंप, सुनामी और चक्रवातों के लिए पैरामीट्रिक ट्रिगर्स का उपयोग करते हुए, यह पुनर्बीमा बाजारों और कैटास्ट्रॉफी स्वैप लेन-देन के माध्यम से बजट के लचीलेपन को बढ़ाता है।
- अफ्रीकन रिस्क कैपेसिटी - ARC, अफ्रीका (2014): सूखे से संबंधित खाद्य असुरक्षा के लिए तत्काल फंड जारी करने के लिए सैटेलाइट मौसम निगरानी का उपयोग करता है, क्षेत्रीय जोखिम पूलिंग के माध्यम से 50% तक की बचत हासिल करता है।

प्रगति के बावजूद, भारत की आपदा जोखिम वित्तपोषण यात्रा में अभी भी कई बड़ी रुकावटें हैं। इनमें कम बीमा कवरेज (कुछ योजनाओं के लिए अभी लगभग 35%), सीमित जन जागरूकता, और सरकारी वित्तीय साधनों की जटिलता शामिल है। आगे बढ़ते हुए, आपदा जोखिम वित्तपोषण को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं -

1. डेटा की गुणवत्ता को मजबूत करना : जोखिम मूल्यांकन और मॉडलिंग को बेहतर बनाने के लिए खतरे और जोखिम के आंकड़ों में निरंतर सुधार करना।
2. पैरामीट्रिक समाधानों का विस्तार करना : ऐसे उपकरण विकसित करना जो त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भौतिक मापदंडों (जैसे हवा की गति या वर्षा) के आधार पर स्वचालित भुगतान शुरू करें।
3. संस्थागत क्षमता बढ़ाना : जटिल जोखिम हस्तांतरण साधनों को प्रबंधित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और स्थानीय निकायों के भीतर तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण करना।

इन रणनीतियों को एकीकृत करके, भारत एक प्रतिक्रियाशील ''राहत-केन्द्रित'' मॉडल से एक समुत्थानशील, ''जोखिम के प्रति जागरूक'' अर्थव्यवस्था में बदल सकता है जो बदलती जलवायु और आपदा जोखिमों के बढ़ते खतरों से अपनी सबसे कमजोर आबादी की रक्षा करने में सक्षम हो।

एनआईडीएम डिजिटल लर्निंग ड्राइव: आपदा-रोधी भारत के लिए डिजिटल लर्निंग

सुश्री नाज़िया खान
प्रभारी, ई-लर्निंग

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) में शिक्षा केवल कक्षा की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसे एक सतत् यात्रा के रूप में देखा जाता है, जो जागरूकता बढ़ाती है, तैयारी को प्रोत्साहन देती है, और संस्थानों और समुदायों दोनों को सशक्त बनाती है। माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 10-सूत्रीय एजेंडा के अनुरूप, NIDM नवाचार, समावेशन और तकनीक के उद्देश्यपूर्ण उपयोग के माध्यम से भारत के प्रतिरोधक क्षमता के एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। इस प्रयास का मुख्य बिंदु एजेंडा प्वॉइंट 6 है- आपदा जोखिम प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग। यह सिद्धांत एनआईडीएम की डिजिटल परिवर्तन पहलों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है।

iGOT कर्मयोगी (https://igotkarmayogi.gov.in/) पर एनआईडीएम के जीवंत एवं स्व-गतिशील पाठ्यक्रम वास्तविक दुनिया की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें व्यावहारिकता, नीति प्रासंगिकता और शासन संदर्भों में सीधे उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य आकर्षण में आपदा तैयारी के लिए क्या करें और क्या न करें, बाढ़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की मूल बातें और भीड़ प्रबंधन शामिल हैं, जो जोखिम संचार, सामुदायिक तैयारी और पूर्वानुमानित कार्रवाई को मजबूत करते हैं। कोर्स पोर्टफोलियो में स्कूल सुरक्षा पर केंद्रित मॉड्यूल भी शामिल हैं, जिसमें खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता विश्लेषण और योजना और संरचनाओं से परे शमन शामिल हैं। सामूहिक रूप से, ये कोर्स अंग्रेजी और विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रभावी, जोखिम के प्रति जानकारी युक्त आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान और परिचालन अंतर्दृष्टि दोनों प्रदान करते हैं।

अपने बढ़ते iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, NIDM सरकारी तंत्र में निरंतर सीखने की संस्कृति को मजबूत कर रहा है, जो नीतिगत इरादे को प्रशासनिक तत्परता और सूचनायुक्त कार्रवाई में बदलता है। आपदा प्रतिरोधकता को दैनिक शासन दक्षताओं में शामिल करके, ये पहल जोखिम का अनुमान लगाने, प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने और आपदा से निपटने के स्थायी उपाय करने के लिए भारत की संस्थागत क्षमता को मजबूत कर रही हैं।

क्रमांक	विषय का नाम	भाषा	अवधि (घंटा:मिनट)	नामांकित	पूर्ण किए	सामग्री रेटिंग	अंतिम प्रकाशन तिथि
1	आपदा प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत	गुजराती	01:35:00	197	95	4.6	03-06-2025
		मलयालम	01:35:00	245	98	4.7	15-05-2025
		तमिल	01:35:00	678	236	4.5	03-10-2025
		हिंदी	01:35:00	1677	576	4.3	15-05-2025
		अंग्रेज़ी	01:35:00	4263	1454	4.3	07-10-2024
		तेलुगू	01:35:00	15355	8192	4.4	15-05-2025
		बंगाली	01:35:00	320	126	4.6	31-07-2025
2	आपदा तैयारी के लिए क्या करें और क्या न करें	तेलुगू	01:08:00	14427	8413	4.5	15-05-2025
		तमिल	01:06:00	252	116	4.7	27-08-2025
		गुजराती	01:05:00	285	126	4.7	03-06-2025
		बंगाली	01:06:00	476	222	4.5	31-07-2025
		हिंदी	01:08:00	1547	635	4.4	15-05-2025
		अंग्रेज़ी	01:05:00	5905	3463	4.2	07-10-2024
		मलयालम	01:04:00	280	113	4.7	15-05-2025
3	बाढ़ प्रबंधन	अंग्रेज़ी	00:35:00	10137	5882	4.3	11-10-2024
		तमिल	00:33:00	435	218	4.7	27-08-2025
		हिंदी	00:35:00	32221	18039	4.2	15-05-2025
		बंगाली	00:35:00	666	340	4.5	31-07-2025
		गुजराती	00:35:00	392	174	4.5	03-06-2025
		तेलुगू	00:35:00	30410	18458	4.3	15-05-2025
		मलयालम	00:35:00	1389	532	4.5	15-05-2025
4	भीड़ प्रबंधन	अंग्रेज़ी	01:45:00	7272	4814	4.4	02-05-2025
5	स्कूल सुरक्षा:आपदा जोखिम संवेदनशीलता विश्लेषण	अंग्रेज़ी	01:35:00	4059	2427	4.1	02-06-2025
6	संरचनाओं से परे स्कूल सुरक्षा योजना और शमन	अंग्रेज़ी	01:40:00	1538	505	4.4	02-07-2025
				134426	75254		

यूट्यूब लिंक : https://www.youtube.com/@NIDMINDIA

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 5वां समग्र पाठ्यक्रम, 06-17 अक्टूबर 2025

नाम: मो. वलीउल्लाह
पदनाम: फ्रीलांस कंसल्टेंट (विकास अनुभाग)
राज्य: उत्तर प्रदेश

यह कोर्स सच में मेरी आँखें खोलने वाला रहा। इसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दुनिया में नए दृष्टिकोण और गहरी समझ दी। हर सेशन ने समझ की एक नई परत जोड़ी, जिससे हमें डीआरआर को उन आयामों से देखने में मदद मिली जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था।

इतनी सार्थक वर्कशॉप आयोजित करने के लिए NIDM और पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। डॉ. प्रेरणा मैम और डॉ. अर्कप्रभा सर, लाइब्रेरी टीम और उनकी पूरी समर्पित टीम को विशेष धन्यवाद, सुबह के लेक्चर से लेकर देर रात के बैडमिंटन मैचों तक, आपकी लगातार उपस्थिति और ऊर्जा ने इस कोर्स को सच में यादगार बना दिया। जीवंत बातचीत और सीखने के लिए सभी प्रतिभागियों का आभारी हूँ। आप सभी के साथ सीखना और जुड़ना खुशी की बात थी।

नाम: डॉ. एन. दर्गा कुमार
पदनाम: जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
राज्य: आंध्र प्रदेश

आपदाओं और उनके जोखिम प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए NIDM और उसके कर्मचारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर, डॉ. प्रेरणा और डॉ. अर्कप्रभा सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने कोर्स को इतनी सहजता और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए अथक प्रयास किए।

सभी मिलनसार प्रतिभागियों को हार्दिक धन्यवाद।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 6वां समग्र पाठ्यक्रम, 06-17 अक्टूबर 2025

नाम: डॉ. रोशनी पटेल
पदनाम: असिस्टेंट प्रोफेसर (भूविज्ञान विभाग),
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा
राज्य: कर्नाटक

''NIDM में आपदा जोखिम प्रबंधन पर छठे व्यापक पाठ्यक्रम में भाग लेना सच में एक ज्ञानवर्धक अनुभव था। ट्रेनिंग में सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक अनुभव के बीच सही संतुलन था। जोखिम मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और GIS-आधारित आपदा मैपिंग पर सत्र मेरे भूविज्ञान के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और NDRF टीमों के साथ बातचीत से मुझे यह समझने में मदद मिली कि वास्तविक दुनिया की आपदा स्थितियों में विज्ञान और फील्ड की तैयारी कैसे एक साथ काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ प्राप्त ज्ञान और कौशल आपदा समुत्थानशीलता पर मेरे शिक्षण और अनुसंधान को बहुत बढ़ाएंगे।''

नाम: श्री योगेश चौहान
पदनाम: सचिव, राज्य खाद्य आयोग,
राज्य: हिमाचल प्रदेश

''NIDM की ट्रेनिंग मेरे लिए सच में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, जिससे मुझे आपदा जोखिम प्रबंधन के बहुआयामी स्वरूप के बारे में गहरी जानकारी मिली। सेशन में कई तरह के टॉपिक शामिल थे – DM एक्ट 2005 के तहत कानूनी और संस्थागत ढांचे से लेकर फर्स्ट एड, लोगों को निकालने और इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर प्रैक्टिकल डेमो तक। अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर खास ज़ोर दिया गया, जो बहुत फायदेमंद था। IDRN और SACHET, CAP, और NDEM जैसे अलग-अलग प्रारंभिक चेतावनी पोर्टल का इस्तेमाल इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के ज़रिए समझाया गया, जिससे इमरजेंसी के दौरान इन टूल्स का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिली। ग्रुप एक्सरसाइज और NDRF के डेमो ने असल दुनिया की स्थितियों में तैयारी और टीम वर्क के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाया। मैं इस कोर्स से मिली सीख को अपने विभाग और समुदाय में आपदा प्रबंधन की पहलों को मज़बूत करने के लिए लागू करने की उम्मीद करता हूँ।''

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 5वां समग्र पाठ्यक्रम, 06-17 अक्टूबर 2025

नामः *डॉ. मोहित शर्मा*
पदनामः *2IC/मेडिकल, 12BN NDRF*
राज्यः *ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश*

मैं NIDM, दिल्ली में आपदा जोखिम प्रबंधन पर हाल ही में हुए व्यापक कोर्स के दौरान मिले शानदार अनुभव के लिए सच में आभारी हूँ। डॉ. पंकज कुमार को इतने अच्छे से व्यवस्थित, जानकारीपूर्ण और व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष धन्यवाद, जिसने मेरी समझ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। पूरी NIDM टीम, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ को कोर्स को इतनी सफलतापूर्वक आयोजित करने और पूरे समय बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में मूल्यवान नई जानकारी मिली, साथ ही तैयारी, रोकथाम, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के बाद के उपायों के बारे में भी, जिनमें से कई पहलू मेरे लिए बिल्कुल नए थे। सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा का सही संतुलन, खासकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों ने मुझे सामाजिक मुद्दों को आपदा प्रबंधन के नज़रिए से देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र (NCS) के फील्ड दौरे विशेष रूप से ज्ञानवर्धक थे और जहां से बहुत अधिक व्यावहारिक मिली। अंत में, मैं अपने सभी सह-प्रतिभागियों को उनके सक्रिय योगदान, अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों को खुलकर साझा करने और इतने सकारात्मक, उत्साही, अनुशासित और सुखद सीखने का माहौल बनाने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह प्रशिक्षण बहुत फायदेमंद रहा है और निस्संदेह मेरे पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एक बार फिर धन्यवाद!

नाम : *ज़िया उल हक़*
पदनामः *पुलिस उप-अधीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस*
राज्यः *जम्मू एवं कश्मीर*

मैंने हाल ही में एनआईडीएम, नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 7वाँ समग्र पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है और उस पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ:

- विषयवस्तु एवं संरचना : पाठ्यक्रम, थ्योरी और प्रैक्टिकल अभ्यासों के बीच अच्छी तरह से संतुलित था। हाल की भारतीय आपदाओं के केस स्टडीज़ ने वास्तविक दुनिया की स्थिति से अवगत कराया।
- संकाय : रिसोर्स पर्सन अत्यंत जानकार थे और उन्होंने चर्चा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से अहम भूमिका निभाई। शंकाओं के समाधान के प्रति उनकी तत्परता ने जटिल अवधारणाओं को आसान बनाने में मदद की।
- अध्ययन सामग्री : रीडिंग पैक और वीडियो मॉड्यूल अद्यतन और सहज रूप से उपलब्ध थे। सभी प्रस्तुतियों की डिजिटल कॉपी संदर्भ के लिए उपयोगी साबित हुए।
- व्यावहारिक सत्र : फील्ड ड्रिल और जीआईएस मैपिंग अभ्यास प्रमुख आकर्षण रहे, जो जोखिम आकलन उपकरणों के प्रयोग के लिए अत्यंत उपयोगी थे।

इतने मूल्यवान कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 8वां व्यापक कोर्स, 17-28 नवंबर, 2025

नामः *तापती राज*
पदनामः *डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपातकालीन अधिकारी, नयागढ़*
राज्यः *ओडिशा*

NIDM द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन पर यह व्यापक ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरह से तैयार की गई थी कि इसने हमें सीखने का एक पूरा अनुभव दिया, जिसमें ग्रुप एक्टिविटी के लिए एक प्लेटफॉर्म भी शामिल था, जिससे अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने में मदद मिली। हमने विशेषज्ञों से ज्ञान सीखा, दूसरे राज्यों से बेहतरीन तरीके सीखे, अलग-अलग फील्ड अधिकारियों से समाधान-केन्द्रित दृष्टिकोण सीखे, शोधकर्ताओं को फीडबैक दिया, IMD, NCS और NDRF 8वीं बटालियन में जाने का मौका मिला, एक मजबूत समाज बनाने के लिए आपदा प्रबंधन के अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला और इसने हमें अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने के लिए लक्ष्य और विज़न तय करने में मदद की है।

नामः *सुश्री श्रीतपा मिश्रा*
पदनामः *डिप्टी कलेक्टर, ओडिशा प्रशासनिक सेवा, खुर्दा*
राज्यः *ओडिशा*

मुझे DRR पर 8वें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में शामिल होने का मौका मिला, और मुझे कहना होगा कि यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव था। फैकल्टी बहुत शानदार थी, और पाठ्यक्रम व्यापक और अच्छी तरह से व्यवस्थित था। कोर्स में आपदा जोखिम मूल्यांकन से लेकर शमन रणनीतियों तक कई तरह के विषयों को शामिल किया गया था, और भारतीय हिमालयी क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। कोर्स का सबसे अच्छा हिस्सा प्रैक्टिकल लर्निंग और केस स्टडीज़ पर ज़ोर देना था। इंटरैक्टिव सेशन और ग्रुप डिस्कशन ने मुझे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद की और वास्तविक दुनिया के हालात में लागू करने में इससे हमें सहायता मिलेगी। लाइब्रेरी बहुत उपयोगी और अच्छी तरह से सुसज्जित है। मैं NIDM टीम के ऐसे मूल्यवान कोर्स को आयोजित करने के प्रयासों की सराहना करती हूँ। मैंने जो ज्ञान और कौशल हासिल किए हैं, वे मुझे अपने समुदाय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों में योगदान देने के लिए तैयार किया है।

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 9वां व्यापक कोर्स, 01-12 दिसंबर 2025

***नाम:* डॉ. ऋचा आहूजा**
***पदनाम:* सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स (COESEA) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर**
***राज्य:* पश्चिम बंगाल**

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दो सप्ताह का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अत्यंत सुव्यवस्थित, बौद्धिक रूप से बेहतरीन और समकालीन विकास चुनौतियों के लिए बहुत प्रासंगिक था। मैं NIDM के फैकल्टी को बधाई देती हूँ जिन्होंने कोर्स को कुशलता से डिज़ाइन और प्रस्तुत किया। कोर्स संरचना ने कमजोर समुदायों पर प्रभाव के लिए फ्रेमवर्क को सफलतापूर्वक एकीकृत किया। हमें फील्ड विजिट के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला कि कैसे NDMA नीतिगत निर्णय लेता है जो वास्तविक प्रभाव डालते हैं, कैसे IMD सैटेलाइट डेटा प्राप्त करता है और तैयारी, शमन के बारे में सूचित करने के लिए अपने स्थानीय सेंसर के साथ एकीकृत करता है, और यह भी कि NDRF आपदा क्र समय कैसे प्रतिक्रिया करता है। मेरे लिए, यह कोर्स अपने सिस्टम दृष्टिकोण, व्यावहारिक उपकरणों और वास्तविक दुनिया के केस स्टडी के लिए सबसे अलग था। मैंने इस कार्यक्रम को शिक्षण, अनुसंधान और नीतिगत जुड़ाव के लिए बहुत समृद्ध पाया, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रतिबद्ध शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और प्रैक्टिसनर्स के लिए इसकी अनुशंसा करती हूं। मुझे इस क्षेत्र में सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए IIT खड़गपुर और NIDM की आभारी हूँ।

***नाम:* श्री जितेंद्र शर्मा**
***पदनाम:* बटालियन प्रशासनिक अधिकारी, 6वीं बटालियन मंडी होमगार्ड, SDRF, फायर सर्विसेज और सिविल डिफेंस, मंडी**
***राज्य:* हिमाचल प्रदेश**

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 9वां व्यापक कोर्स 01 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह कोर्स देश भर के विभिन्न कैडर के अधिकारियों के कौशल और समझ को बढ़ाने के लिए असाधारण रूप से अच्छा था, जिससे कि वे आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को गहराई से समझ सकें। NIDM फैकल्टी, स्टाफ और प्रशासन के सभी लोगों द्वारा किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। IMD, NDMA और NDRF में प्रस्तुतियों और विचार-मंथन सत्रों के दौरान मूल्य संवर्धन सत्र भी उल्लेखनीय हैं। ऐसे कोर्स का आयोजन और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अवधारणा में निरंतर अपडेशन निश्चित रूप से उन प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाने के लिए फायदेमंद होंगे जो वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपदा राहत से संबंधित गतिविधियों के विभिन्न चरणों से निपटते हैं।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 5वां समग्र पाठ्यक्रम, 06-17 अक्टूबर 2025

***नाम:* डॉ. बी. जगदीश्वर कुमार**
***पदनाम:* पशु चिकित्सा सहायक सर्जन, पशुपालन विभाग**
***राज्य:* आंध्र प्रदेश**

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में, मैंने कई नए और महत्वपूर्ण विषय सीखे, विशेष रूप से मनोसामाजिक तकनीकें, जो आपदा प्रबंधन का एक अनदेखा लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है। मुझे आपदा वित्त और फंड आवंटन की भी स्पष्ट समझ मिली, जिसमें यह भी शामिल है कि बजट केन्द्र से राज्य स्तर तक कैसे प्रवाहित होता है। PDNA और HRVCA पर सत्रों ने एक व्यापक वैचारिक समझ प्रदान की, जबकि NDRF के दौरे ने बचाव तकनीकों और उपकरणों में मूल्यवान जानकारी प्रदान की। कुल मिलाकर, प्रशिक्षण ने आपदा पीड़ितों के साथ काम करने के मेरे ज्ञान, व्यावहारिक समझ और दृष्टिकोण को बढ़ाया। मैं अपने मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सभी संकाय सदस्यों को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं।

***नाम:* सुनील भगत**
***पदनाम:* सहायक प्रोफेसर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय**
***राज्य:* आंध्र प्रदेश**

NIDM दक्षिण परिसर में आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 12-दिवसीय व्यापक पाठ्यक्रम में भाग लेना एक शानदार और पेशेवर रूप से परिवर्तनकारी अनुभव था। कार्यक्रम ने वास्तविक भारतीय आपदा संदर्भों पर आधारित सिद्धांत, केस स्टडी और क्षेत्र-आधारित अंतर्दृष्टि का एक मजबूत मिश्रण प्रदान किया। इसने जोखिम मूल्यांकन, तैयारी, शमन और संस्थागत समन्वय की मेरी समझ को काफी मजबूत किया। संकाय की विशेषज्ञता और सहकर्मियों से सीखने के तरीके ने पाठ्यक्रम को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के लिए व्यावहारिक और प्रभावशाली बनाया।

वेबिनार

17 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण पर वेबिनार

क्रम संख्या	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	माह	संकाय
1	आंध्र प्रदेश	03-05 नवंबर 2025 (प्रशिक्षण)	NIDM, दक्षिणी परिसर, आंध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश	24 अक्टूबर 2025	NIDM, दिल्ली
3	मेघालय	24 अक्टूबर 2025	NIDM, दिल्ली
4	असम	27 नवंबर 2025	NIDM, दिल्ली
5	मणिपुर	21 नवंबर 2025	NIDM, दिल्ली
6	मिजोरम	21 नवंबर 2025	NIDM, दिल्ली
7	त्रिपुरा	29 दिसंबर 2025	NIDM, दिल्ली
8	बिहार	03 दिसंबर 2025	NIDM, दक्षिणी परिसर, आंध्र प्रदेश
9	झारखंड	03-05 नवंबर 2025 (प्रशिक्षण)	NIDM, दिल्ली
10	गुजरात	03-05 सितंबर 2025	NIDM, दिल्ली
11	हिमाचल प्रदेश	26 नवंबर 2025	NIDM, दिल्ली
12	कर्नाटक	22 दिसंबर 2025	NIDM, दिल्ली
13	महाराष्ट्र	01 दिसंबर 2025	NIDM, दक्षिणी परिसर, आंध्र प्रदेश
14	ओडिशा	22 दिसंबर 2025	NIDM, दिल्ली
15	सिक्किम	22-24 अप्रैल 2025 (प्रशिक्षण)	SIRD, सिक्किम
16	तमिलनाडु	18 दिसंबर 2025	NIDM, दक्षिणी परिसर, आंध्र प्रदेश
17	पुडुचेरी	18 दिसंबर 2025	NIDM, दक्षिणी परिसर, आंध्र प्रदेश
18	उत्तराखंड	19 दिसंबर 2025	NIDM, दिल्ली
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30 दिसंबर 2025	NIDM, दिल्ली
20	लक्षद्वीप	30 दिसंबर 2025	NIDM, दिल्ली
21	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	16 दिसंबर 2025	NIDM, दिल्ली

एनआईडीएम प्रकाशन

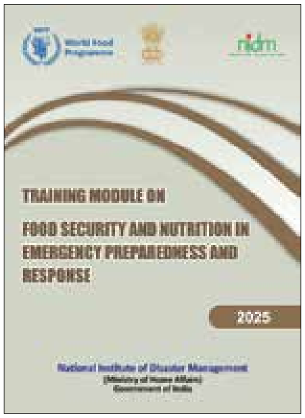

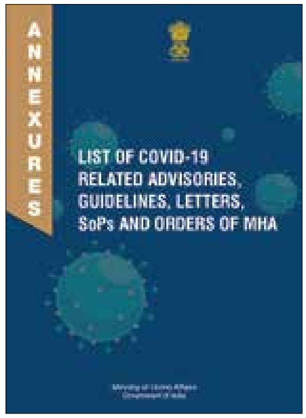

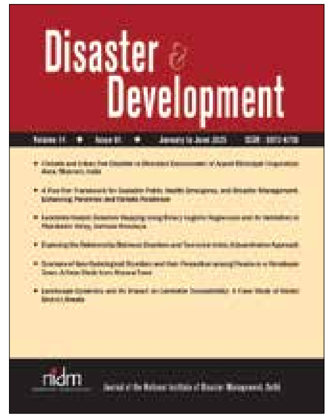

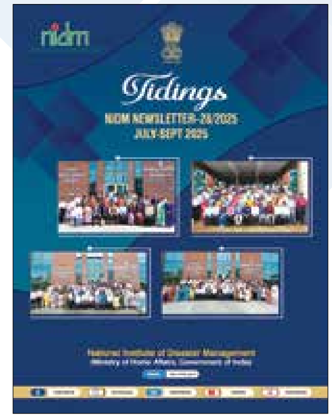

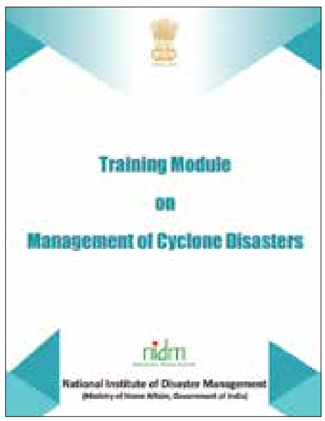

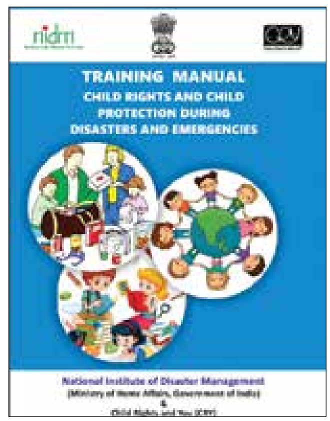

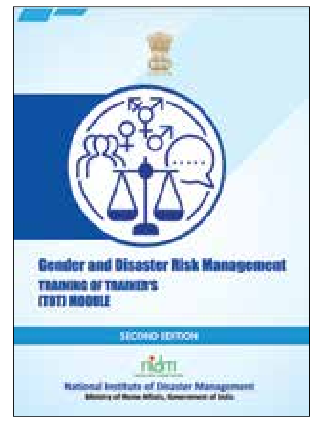

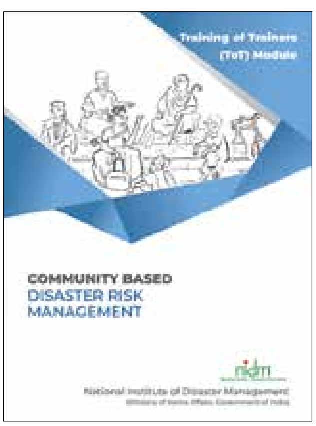

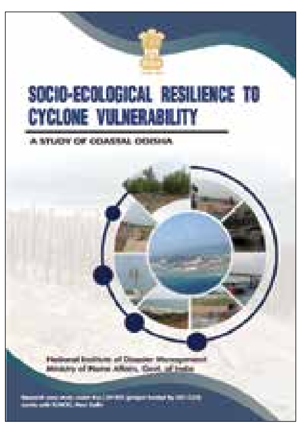

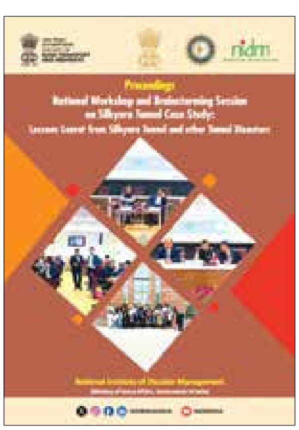

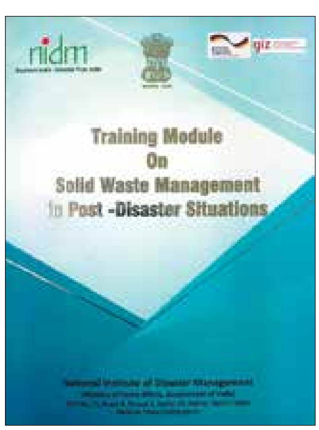

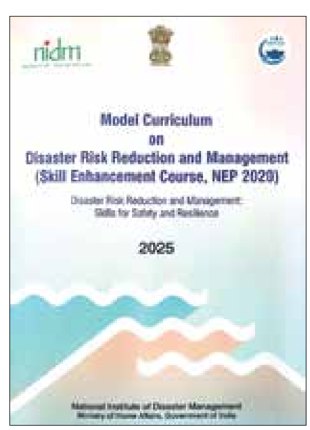

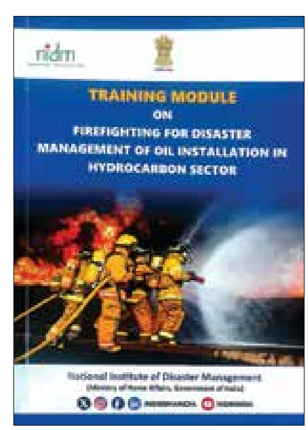

एनआईडीएम पोर्टल्स

वर्ष 2025–26 के दौरान एनआईडीएम द्वारा आयोजित एवं प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

nidm

Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नं. 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली-110042

वेबसाइट : www.nidm.gov.in